an>

Title: Need to install advance warning system to deal with natural calamities in the country.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हिमालय भारत का माथा कहा जाता है। हिमालय केवल इस देश की ही नहीं, बल्कि विश्व की धरोहर है। आज वह तमाम संकटों से गुजर रहा है। मैं यह समझता हूँ कि चाहे भारत की संस्कृति का प्राण हो, चाहे सीमाओं की रक्षा का विषय हो, चाहे आयुष, संजीवनी बूटी और आयुर्वेद का जन्मदाता हो, चाहे एशिया का वाटर टावर हो, चाहे पर्यावरण के संशोधन की दिशा हो, चाहे देश के लोगों को प्राण वायु देता हो, आज पूरा हिमालय का क्षेत्र आपदा की मार झेल रहा है, पलायन की मार को झेल रहा है, आर्थिक विपन्नता को झेल रहा है और इस स्थिति में आ गया है कि सैकड़ों गांवों का नामोनिशान मिट गया है। वे आपदाएँ चाहे वर्ष 1991 में उत्तरकाशी-रुद्र प्रयाग में आया हो, चाहे वर्ष 2010 में पूरे उत्तराखण्ड में आया हो, चाहे वर्ष 2013 में केदारनाथ में आयी हो, जिसमें हजारों लोग मरे हैं, वह इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसमें आज तक लोगों के शव मिल रहे हैं, हजारों लोग लापता हुए, हजारों लोगों के शव दिखायी दिये, आज भी लोग जगह-जगह भटकते हुए मिल रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड की सरकार टोटली फेल है। केन्द्र सरकार को अपने हाथ में कुछ-न-कुछ लेना पड़ेगा और जो ऐसी आपदाएँ हैं, जिनके कारण पर्यटन में 12 हजार करोड़ रुपए की क्षति अकेले उत्तराखण्ड को हुई और दस हजार से भी अधिक लोग मरे। जम्मू-कश्मीर में दो हजार छः सौ से अधिक गांव प्रभावित हुए, पांच हजार सात सौ करोड़ रुपयों की आर्थिक क्षति हुई है। हिमालय की इस पूरी बैल्ट के लिए अलग नीति हर हाल में बनानी होगी। सूचना तंत्र के अभाव में यह त्रासदियां हो रही हैं। देश का 58.6 प्रतिशत हिस्सा भूकम्प के खतरों से ग्रस्त है। भारत में लगभग छह करोड़ लोग प्रति वर्ष आपदा से प्रभावित हो रहे हैं। देश में 68 प्रतिशत भूभाग सूखे की चपेट के खतरे में रहता है। हिमालय क्षेत्र चाहे उत्तराखंड का हो या हिमाचल का हो या पूर्वोत्तर राज्य हों या जम्मू-कश्मीर हो, शत-प्रतिशत आपदा के खतरों को झेल रहा है।

उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है और इसके उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए पूर्व चेतावनी तंत्र को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी शुरू में ही होनी चाहिए। समन्वय का जो अभाव है, इसकी तरफ समय रहते पूरा ध्यान देना चाहिए। जो राहत कार्य बहुत धीमी गति से हो रहे हैं, इनके कारण बहुत क्षति होती है। संसाधनों का कुप्रबंधन होता है, प्रशासन की निष्क्रियता होती है और संचार तंत्र तथा सूचना तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि हिमालय में डोपलर रडार की स्थापना होनी चाहिए। वॉटर पल्स स्केल की स्थापना होनी चाहिए। वज्रपात संवेदन यंत्र की स्थापना होनी चाहिए। केंद्र स्तर पर एक ऐसी ईकाई स्थापित होनी चाहिए जो प्रभावी तरीके से इसका अनुसंधान करे।

माननीय **उपाध्यक्षः**

श्री अनुराग ठाकुर और

श्री अर्जुन मेघवाल अपने आपको डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करते हैं।